



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251।

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933

No. 251।

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 286(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (इसमें इसके पश्चात् संस्था कहा गया है) को प्राधिकृत करती है कि वह वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एक सार्वजनिक निर्गम द्वारा नियमित विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तीन हजार करोड़ रुपये की कुल राशि के 1,000-1,000 रुपये के कर-मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांडों को जारी करेगा :—

- (क) बांडों की अवधि : बांडों की अवधि दस अथवा पन्द्रह वर्ष होनी चाहिए;
- (ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) : उपभोक्ताओं के लिए उनके निर्गमकर्ताओं को पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा;
- (ग) ब्याज की दर : बांडों पर ब्याज नियत आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ द्वारा बताए गए अनुसार बांडों के निर्गम के माह से तुरंत पहले वाले माह के अंतिम कार्य दिवस पर पचास आधार अंकों से अधिक तथा समतुल्य अवशिष्ट परिणवता की सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्ति से कम होना चाहिए ;

बशर्ते कि अर्हक संस्थागत क्रेता (क्यू आई बी), निर्गम एवं उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टियों (एच एन आई) को प्रस्तावित दर की तुलना में खुदरा व्यष्टिगत निवेशक को 20 आधार अंकों तक की उच्चतर कूपन दर का प्रस्ताव दिया जा सकता हो :

बशर्ते यह भी कि मूल निवेशक की मृत्यु होने पर विधिक वारिस को हस्तांतरण के मामले के अलावा बांडों के हस्तांतरण के मामले में ब्याज की उच्चतर दर उपलब्ध नहीं होगी :

- (घ) विक्रय पर कमीशन—(i) विक्रय पर कमीशन की अधिकतम राशि निर्गम के आकार के 1.25 प्रतिशत की एक समान शुल्क पर नियंत की जाएगी;
- (ii) एक समान शुल्क में बांडों के निर्गम हेतु हुआ कुल व्यय शामिल होगा जिसमें विज्ञापन, दलाली, मुद्रण, संग्रहण प्रचार शुल्क रोड प्रदर्शन पर होने वाला व्यय तथा इस प्रक्रिया में खर्च होने वाले अन्य शुल्क शामिल हैं;
- (iii) बशर्ते कि अर्हक संस्थागत क्रेता एवं निगम के मामले में दलाली 0.15 प्रतिशत तथा उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टियों के मामले में 0.35 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (ड) उक्त धारा के अंतर्गत हितलाभ तभी स्वीकार्य होगा जब ऐसे बांडों का धारक अपना अथवा उसका नाम तथा धारिता को संस्था के साथ पंजीकृत करवाता है।
- (च) संस्था बांडों का निर्गम केवल सार्वजनिक निर्गम द्वारा करेगी न कि निजी स्थापन के माध्यम से।

[अधिसूचना सं. 07/2012/फा. सं. 178/56/2011-(आ.क.नि.-I)]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-I)

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,—

- (i) अर्हक संस्थागत क्रेता एवं खुदरा व्यष्टिगत निवेशक का अर्थ वही होगा जो अर्थ उनके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रकटन एवं निवेशक सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 में दिया गया है।
- (ii) एक लाख रुपये से अधिक निवेश करने वाले किसी व्यष्टि निवेशक को उच्च निवल मूल्य वाला व्यष्टि माना जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 286(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the Rural Electrification Corporation (hereinafter referred to as the entity), to issue, through a public issue, during the financial year 2011-12, tax free, secured, redeemable, non-convertible bonds of Rupees 1,000 each, aggregating to Rupees three thousand crores subject to the conditions specified namely:—

- (a) Tenure of Bonds : The tenure of the bonds shall be ten years or fifteen years;
- (b) Permanent Account Number (PAN) : It shall be mandatory for the subscribers to furnish their PAN to the issuer;
- (c) Rate of Interest : The interest on the bonds shall be not less than fifty basis points lower than the yield on the Government Securities of equivalent residual maturity as reported by the Fixed Income Money Market and Derivative Association of India, as on the last working day of the month immediately preceding the month of the issue of the bonds :

Provided that a higher coupon rate of up to 20 basis points may be offered to Retail Individual Investor vis-a-vis the rate offered to Qualified Institutional Buyers (QIBs), corporate and High Networth Individuals (HNIs) :

Provided further that higher rate of interest shall not be available in case the bonds are

transferred, except in case of transfer to legal heir in the event of death of the original investor;

- (d) Commission on sale.—(i) the commission on sale shall be capped at a maximum of a flat fee of 1.25% of the issue size;
- (ii) The flat fee shall include the total expense for the issue of bonds, including the expenses for advertisement, brokerage, printing, collection, canvassing charges, road shows and all other charges spent for this process.
- (iii) Provided that the brokerage shall not exceed 0.15 per cent in the case of Qualified Institutional Buyers and corporate and 0.35 per cent in the case of High Networth Individuals.
- (e) The benefit under the said section shall be admissible only if the holder of such bonds registers his, her or it's name and the holding with the entity.
- (f) The entity shall issue the bonds only by way of public issue, and not by way of private placement.

[Notification No. 07/2012/F. No. 178/56/2011- (ITA. I)]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA. I)

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) Qualified Institutional Buyers and Retail Individual Investors shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
- (ii) Any individual investor investing more than Rupees one lakh shall be treated as High Networth Individual.